

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2896

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

गायब कंपनियां

2896. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

डा. मुरली मनोहर जोशी :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास शुरू में 283 कंपनियों के गायब होने की सूचना थी;
- (ख) यदि हां, तो आम निवेशकों द्वारा इन कंपनियों में कितनी निधि का निवेश किया गया था;
- (ग) क्या उपर्युक्त में से 151 कंपनियों ने संबंधित विभागों को सूचना दी हैं;
- (घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और उन्हें आम निवेशकों से कितनी धनराशि मिली है; और
- (ड.) निवेश के समय से इनमें से प्रत्येक कंपनी के शेयर मूल्य में कितनी कमी आई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.) : प्रारंभ में ऐसी 238 कंपनियों की पहचान की गई [जिन्होंने पब्लिक इश्यु के माध्यम से राशि की उगाही की थी]। इनमें से 119 कंपनियों को सूची से हटा दिया गया था और 'निगरानी सूची' में रखा गया था, क्योंकि इन कंपनियों ने कंपनी रजिस्ट्रारों/स्टॉक एक्सचेंजों में अपने दस्तावेज/तुलन पत्र आदि दायर करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त, फिलहाल 32 कंपनियां परिसमापनाधीन हैं। इस प्रकार वर्तमान

में 87 कंपनियों को लुप्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 87 कंपनियों द्वारा प्राप्त पब्लिक इश्यु की कुल राशि 341.90 करोड़ रुपए (लगभग) है।

\*\*\*\*\*